



जिला-अल्मोड़ा के इण्टरमीडिएट स्तर के छात्र-छात्राओं का जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन।

डॉ. राजेन्द्र सिंह पथनी¹, देवेन्द्र सिंह चम्माल²

¹प्रोफेसर, संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, परिसर निदेशक, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल।

²एम० एस-सी० रसायन विज्ञान, एम० ए० गणित, एम० ए० इतिहास, एम० एड० (गोल्ड मैडलिस्ट), नेट (शिक्षाशास्त्र), भोध छात्र एवं अतिथि व्याख्याता, शिक्षा संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल।

सारांश-

वर्तमान में जनसंख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि एक ज्वलन्त मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती के रूप में हमारे सामने एक विकराल रूप ले कर खड़ी है। इस समस्या से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यह है कि जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित किया जाए और यह तभी सम्भव है जब जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के विषय में प्रचार किया जाये। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। यह कार्य विद्यालय स्तर से किया जाना आवश्यक है ताकि बालकों को प्रारम्भ



से ही जनसंख्या सम्बन्धी मुद्दों की जानकारी प्राप्त हो सके। इण्टरमीडिएट के विद्यार्थी किशोरावस्था के होते हैं और किशोरावस्था में बालकों में भरपूर जोश व उत्साह भरा होता है। वे अपने देश व समाज से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में सोचते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए अपना सहयोग प्रदान करने को उत्सुक रहते हैं। अतः विद्यार्थियों को जनसंख्या शिक्षा प्रदान करके उन्हें जागरुक नागरिक बनाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध समस्या हेतु डा० जी० एस० नयाल, आचार्य, शिक्षा संकाय, एस० एस० जे० परिसर अल्मोड़ा तथा एम०एड० शोधार्थिनी ओजस्वी अग्रवाल द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत जनसंख्या शिक्षा मापनी का प्रयोग किया गया। जनसंख्या शिक्षा मापनी की वैधता 0.58 थी। जनसंख्या शिक्षा मापनी की विश्वसनीयता 0.75 थी। प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अल्मोड़ा जिला के इण्टरमीडिएट में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ प्रस्तुत शोध कार्य की जनसंख्या थी। न्यादर्श हेतु इण्टरमीडिएट के 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य के लिए न्यादर्श का चयन सामान्य यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया।

मुख्य शब्द- जनसंख्या, शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, किशोरावस्था एवं इण्टरमीडिएट।

प्रस्तावना-

वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस हेतु आवश्यक है कि जनसंख्या शिक्षा को

प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा सामाजिक मूल्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता देती है। जनसंख्या शिक्षा द्वारा बालकों में यह धारणा बनायी जा सकती है कि जीवन के स्तर को ऊँचा रखने के लिए परिवार

का सीमित होना आवश्यक है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास कर उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। जनसंख्या

वृद्धि से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जनसंख्या शिक्षा द्वारा ही कराया जाता है। जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या शिक्षा, बालक-बालिकाओं को पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभावों से भी परिचित कराने में सहायक है। इसके अतिरिक्त बालकों में नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने की भावना भी जागृत होती है।

शिक्षा में जनसंख्या के अध्ययन की आवश्यकता सबसे पहले **एल्वा मेयरडेल** ने समझी और उन्होंने 1941 में अपनी पुस्तक “Nation and Family” में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। एल्वा मेयरडेल का उद्देश्य अमेरिकी सरकार को इस बात के लिए तैयार करना था कि परिवार की शिक्षा को राज्य की जनसंख्या नीति में सम्मिलित किया जाए। परन्तु इसके बाद भी दो दशकों तक जनसंख्या सम्बन्धी विषय-वस्तु को विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गए। सन् 1962 में **फिलिप एम. हाउजर** ने अपने लेख “Population Gap in Curriculum” में शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। शिक्षा महाविद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालय के स्लोअन वेलैण्ड ने 1964 में जनसंख्या शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करने का प्रोजेक्ट लिया। स्लोअन वेलैण्ड वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले “जनसंख्या शिक्षा” शब्द का प्रयोग किया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यूनेस्को ने जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं में रुचि लेना प्रारम्भ किया। जनसंख्या के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थामस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या सिद्धान्त प्रतिपादित किया। जनसंख्या शिक्षा में कुछ अध्ययन निम्न हैं:-

Kulshrestha (1990) studied on “A study of the attitude of women teachers towards population education.” They found:

1. Female teachers of the younger age-group (18-28) had a more positive attitude population education than those in the older age-group (40-50).
2. Untrained teachers achieved higher mean attitude scores than trained teachers.
3. Unmarried teachers scored higher attitude scores than married teachers.
4. Hindu women teachers' attitude towards population education was significantly more favourable than that of their Muslim and Christian counterparts.
5. Female teachers teaching Arts subjects scored significantly higher than those teaching science subjects.
6. Higher attitude scores were obtained by rural teachers than by urban teachers.

Manjulavalli (1991) studied on “Population Education awareness among primary school teachers.” They found that the level of knowledge of teachers about population concepts was high and their attitude towards population education was highly favourable.

जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण अनेकों पर्यावरणीय परिवर्तन आये हैं। पानी पीने योग्य नहीं रहा, हवा श्वास लेने योग्य नहीं रही तथा भोजन की गुणवत्ता में कमी आई है और पर्यावरण में असन्तुलन आ गया है। अतः जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के प्रति सभी को सचेत रहना आवश्यक है। यह चेतना जनसंख्या शिक्षा द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि देश के विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा को किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। जनसंख्या शिक्षा का प्रत्यय नवीन है परन्तु इसका उद्भव जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से हुआ है। यह प्रत्यय जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने में भी सहायक है।

इसीलिए प्रस्तुत शोध “जिला अल्मोड़ा के इण्टरमीडिएट स्तर के छात्र-छात्राओं का जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन” द्वारा अल्मोड़ा जिला के इण्टरमीडिएट में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

जनसंख्या नियन्त्रण हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास-

आज विद्यार्थी, अध्यापक तथा समाज के चिंतक शिक्षाशास्त्री आदि सभी मिलकर जनाधिक्य और अशिक्षा की समस्या पर गम्भीर होकर सोचने लगे हैं। जनसंख्या नियन्त्रण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं,

समय-समय पर सरकार ने विभिन्न योजनाएँ बनाकर जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण का प्रयास किया है, इन प्रयासों में से कुछ का विवरण इस प्रकार है—

नई जनसंख्या नीति—

वर्ष 1991 में सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री श्री करुणाकर की अध्यक्षता में जनसंख्या के बारे में एक समिति की नियुक्ति की। वर्ष 1993 में इस समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाए जाने की सिफारिश की गई। 1993 में ही सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निर्धारित करने के लिए डॉ० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। वर्ष 1999 में मन्त्रियों के एक दल ने परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे की जांच की। फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की घोषणा की। इसकी दरम्यानी अवधि का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 2.1 की कुल जनन क्षमता दर प्राप्त करना है। नीतिगत उद्देश्य हासिल करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाएंगे—

- 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना।
- स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़के-लड़कियों की संख्या 20 प्रतिशत से नीचे लाना।
- शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित बच्चों में 30 से कम करना।
- मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख संतानों में एक सौ से कम करना।
- टीकों से रोके जाने वाले रोगों से सभी बच्चों को प्रतिरक्षित करना।
- संक्रामक रोगों को रोकना और उन पर काबू पाना। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को समेकित करना।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग—

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मई 2000 को किया गया। इस आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्तर्गत लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में केन्द्र व राज्य के अभिकरणों द्वारा नागरिक संस्थानों व निजी क्षेत्रों के मध्य समन्वयन करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं की गवेषणा करना था। प्रारम्भ में यह योजना आयोग के अधीन गठित किया गया था किंतु मई 2005 में इसे पुनर्गठित किया गया तथा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री व योजना आयोग के उपाध्यक्ष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए भी यह आयोग विभिन्न विभाग कार्यक्रम चलाएगा। आयोग के उपाध्यक्ष के०सी० पंत के अनुसार जनसंख्या नीति, 2000 लोगों की इच्छा के आधार पर कार्य करेगी तथा शिक्षा व अन्य तरीकों से जनता को जनसंख्या वृद्धि रोकने और परिवार कल्याण के प्रति जागरूक बनाया जाए।

जनसंख्या पूर्वानुमान तकनीकी समूह—

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा मई 2006 में गठित जनसंख्या पूर्वानुमान तकनीकी समूह के अनुसार, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 2006 में समाप्त पांच वर्षों में 1.6 प्रतिशत से धीरे-धीरे कम होते हुए 2026 में समाप्त पांच वर्षों में 0.9 प्रतिशत रह जाने की सम्भावना है। भारत की जनसंख्या, जनगणना 2001 में 1029 मिलियन से बढ़कर 2006 में 1112 होने के अनुमान है और 2026 तक 1400 मिलियन तक वृद्धि होने के पूर्वानुमान हैं।

जनसंख्या स्थिरता कोश—

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अधीन गठित राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष अप्रैल 2002 में परिवार कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा जून, 2003 में इसे जनसंख्या स्थिरता कोष नाम प्रदान किया गया। इस कोष के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयत्नों को मदद प्रदान की जाएगी। इसके द्वारा उन सभी व्यक्तिगत, सामूहिक, सरकारी, गैर-सरकारी व स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जो जनसंख्या स्थिरकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करेंगे। जून 2005 में इसे

पुनर्गठित किया गया तथा स्वास्थ्य मंत्री को इसका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सचिव को प्रबंधक समिति का प्रमुख बनाया गया। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। शिक्षा से जहां जागरुकता को बढ़ावा मिलता है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

समस्या कथन-

जिला-अल्मोड़ा के इण्टरमीडिएट स्तर के छात्र-छात्राओं का जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध समस्या के उद्देश्य-

शोध समस्या के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:-

1. निवास स्थान के आधार पर अर्थात् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शैक्षिक विषय वर्ग के आधार पर अर्थात् कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. अभिभावक की मासिक आय के आधार पर विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अनुसंधान के उपकरण-

प्रस्तुत शोध समस्या हेतु डा० जी० एस० नयाल, आचार्य, शिक्षा संकाय, एस० एस० जे० परिसर अल्मोड़ा तथा एम०एड० शोधार्थिनी ओजस्वी अग्रवाल द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत जनसंख्या शिक्षा मापनी का प्रयोग किया गया, जिसमें 62 प्रश्न थे। इन कथनों में से स्वतन्त्रतापूर्वक किसी एक विकल्प में सही (V) का निशान लगाना था। आपके अनुभव को बताने वाले पाँच विकल्प इस प्रकार हैं। जैसे-पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत। जनसंख्या शिक्षा मापनी की वैधता 0.58 थी। जनसंख्या शिक्षा मापनी की विश्वसनीयता 0.75 थी।

शोध विधि- प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

जनसंख्या- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अल्मोड़ा जिला के इण्टरमीडिएट में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ प्रस्तुत शोध कार्य की जनसंख्या थी।

न्यादर्श- प्रस्तुत शोध कार्य में समय, धन तथा साधनों की सीमाओं को देखते हुए अल्मोड़ा जिला के चार सरकारी विद्यालयों को चुना गया। न्यादर्श हेतु इण्टरमीडिएट के 120 विद्यार्थियों का ही चयन किया गया।

न्यादर्श चयन विधि- प्रस्तुत शोध कार्य के लिए न्यादर्श का चयन सामान्य यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया।

शोध उपकरणों का प्रशासन, अंकन तथा संकलन- शोध उपकरण के रूप में प्रयोग की गई प्रश्नावली को अल्मोड़ा जिला के चार सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 120 विद्यार्थियों के मध्य वितरित किया गया। शोध उपकरणों का अंकन करने के लिए उत्तर मार्गदर्शिका का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक छात्र-छात्रा द्वारा जो प्रश्नावली भरी गयी है अन्त में सही उत्तरों के अंक गिनकर कुल योग प्राप्त किया गया।

प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण- शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ मध्यमान, मानक विचलन तथा "टी" मान का प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा में सार्थक अन्तर ज्ञात करने हेतु 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर टी-मान की गणना की गयी।

शोध परिणामों का प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या- शोध अध्ययन हेतु 120 इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसमें ग्रामीण छात्र-छात्राएँ (50%), शहरी छात्र-छात्राएँ (50%), कला शैक्षिक विषय वर्ग(50.83%), विज्ञान शैक्षिक विषय वर्ग(49.17%), अभिभावक की आय 40,000 से कम(54.16%) एवं अभिभावक की आय 40,000 से ऊपर(45.84%) छात्र-छात्राएँ सम्मिलित थे। जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित आकड़ों का विश्लेषण निम्न है:-

तालिका 1 निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

निवास स्थान	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	60	292	16.31	1.74	सार्थक नहीं
शहरी	60	236	19.28		

D.f. = 118, सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर t-मान सार्थक नहीं ।

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट है कि निवास स्थान के आधार पर विद्यार्थियों के जनसंख्या शिक्षा में कोई सार्थक अन्तर नहीं था (t=1.74)। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा समान पायी गयी। इसका कारण यह हो सकता है कि आज तकनीकी क्रान्ति के समय में शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हो रहा है। सरकार द्वारा किये जा रहे जनसंख्या नियन्त्रण के प्रयासों का शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार होता है जिस कारण शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में भी जनसंख्या शिक्षा का प्रचार हुआ है।

तालिका 2 शैक्षिक विषय वर्ग के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

शैक्षिक विषय वर्ग	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
कला	61	237	15.27	1.35	सार्थक नहीं
विज्ञान	59	241	20.32		

D.f. = 118, सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर t-मान सार्थक नहीं ।

उपरोक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि शैक्षिक विषय वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के जनसंख्या शिक्षा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया (t=1.35)। कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा समान पायी गयी। इसका कारण यह हो सकता है कि कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयों में जनसंख्या शिक्षा का समावेश रहता है। कला वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयों जैसे- समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान आदि विषयों में जनसंख्या शिक्षा का समावेश होता है। इसी प्रकार विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयों जैसे- जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में जनसंख्या शिक्षा के तत्वों का समावेश होता है।

तालिका 3 अभिभावक की मासिक आय के आधार पर जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

अभिभावक की आय	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	सार्थकता स्तर
40,000 से कम	65	241	19.05	1.02	सार्थक नहीं
40,000 से ऊपर	55	236	16.78		

D.f. = 118, सार्थकता स्तर 0.05 तथा 0.01 पर t-मान सार्थक नहीं ।

उपरोक्त तालिका 3 से स्पष्ट है कि अभिभावक की मासिक आय के आधार पर विद्यार्थियों के जनसंख्या शिक्षा प्राप्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया ($t=1.02$)। 40,000 से कम मासिक आय वाले अभिभावकों तथा 40,000 से अधिक मासिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों में समानता पायी गयी। इसका कारण यह है कि निम्न मासिक आय वाले अभिभावक तथा उच्च मासिक आय वाले अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था समान रूप से करते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या शिक्षा के प्रचार व विकास कार्यों को जनता तक सरलता से पहुंचाया जा रहा है।

व्याख्या-

ग्रामीण छात्र-छात्राओं का मध्यमान 292, शहरी छात्र-छात्राओं का मध्यमान 236, कला शैक्षिक विषय वर्ग छात्र-छात्राओं का मध्यमान 237, विज्ञान शैक्षिक विषय वर्ग छात्र-छात्राओं का मध्यमान 241, अभिभावक की आय 40,000 से कम छात्र-छात्राओं का मध्यमान 241 एवं अभिभावक की आय 40,000 से ऊपर छात्र-छात्राओं का मध्यमान 236 था। मध्यमानों में अन्तर पाया गया लेकिन t -मान के आधार पर चरों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा समान पायी गयी। कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा समान पायी गयी। 40,000 से कम मासिक आय वाले अभिभावकों तथा 40,000 से अधिक मासिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों में समानता पायी गयी।

उपसंहार-

- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले विद्यार्थियों के जनसंख्या शिक्षा प्राप्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- कला वर्ग तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
- 40,000 से कम मासिक आय वाले अभिभावकों तथा 40,000 से अधिक मासिक आय वाले अभिभावकों की मासिक आय के आधार पर विद्यार्थियों के जनसंख्या शिक्षा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

जनसंख्या की असमान वृद्धि ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, मानव जीवन के समस्त पहलुओं पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या की गति को रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसके बाद नयी चुनौती के रूप में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम समाज में व्याप्त मूल्यों एवं धारणाओं में परिवर्तन की दिशा में ज्ञानार्जन कराने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रस्तुत लघु शोध के द्वारा जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन के अंतर्गत इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों की जनसंख्या शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या शिक्षा को एक पृथक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को जनसंख्या नियन्त्रण के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक शैक्षिक वर्ग चाहे वह कला हो या विज्ञान, इनके विषयों में जनसंख्या शिक्षा को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा का प्रचार समान रूप से किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों में कुपोषण तथा उससे जनित बीमारियों के कारण उनकी असमय मौतें चिंता का विषय है। इससे भी ग्रामीण परिवारों के बड़े आकार को अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला है परिणामस्वरूप इन परिवारों में अधिक बच्चों का जन्म हो रहा है। इस अवधारणा को बदलने के लिए ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या नियन्त्रण के प्रचार पर बल देना आवश्यक है।

विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत लोगों को भी जनसंख्या नियन्त्रण के विषय में जागरूकता प्रदान करनी चाहिये। शिक्षा द्वारा नागरिकों में दायित्व की भावना विकसित होती है और वे अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। यह दायित्व बोध की अवधारणा ही आगे चलकर आत्मानुशासन एवं आत्मसंयमित जीवन अपनाने में व्यक्ति की सहायता करता है। अतः एक साक्षर व शिक्षित व्यक्ति ही छोटे परिवार के महत्व और लाभों से परिचित हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आर० ए० शर्मा (2011)। शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार। मेरठ: आर० लाल बुक डिपो।
2. उत्तराखण्ड एयर बुक (2011)। देहरादून: विनसर पब्लिशिंग कम्पनी।
3. कपिल, एच०के० & सिंह, ममता (2013)। सांख्यिकी के मूल तत्व। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
4. कोल, ए०जे० & हूवर, ई०एम० (1972)। पॉपुलेशन ग्रोथ एण्ड इकोनॉमिक डेवलपमेन्ट इन लो-इनकम कन्ट्रीज: ए केस स्टडी ऑफ इण्डियाज प्रोस्पेक्ट्स। बॉम्बे: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इण्डियन ब्रांच।
5. कौल, लोकेश (2012)। शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली। नोएडा: विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
6. गुप्ता, एस० (2005)। एजुकेशन इन इमर्जिंग इण्डिया, टीचर्स रोल इन सोशाइटी। दिल्ली: शिप्रा पब्लिकेशन्स।
7. गैरेट, एच०ई० (2000)। शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग। लुधियाना: कल्याणी पब्लिशर्स।
8. चन्देल, एन०पी०एस० & नन्द, वी०के० (2007)। जनसंख्या शिक्षा। आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
9. चन्द्रा, शैलजा (2009)। जनसंख्या स्थिरीकरण: एक साथे सब साथे, योजना। नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार।
10. जायसवाल, अंजली (2008)। बढ़ती जनसंख्या एक समस्या। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मन्त्रालय।
11. बैस्ट, जे० डब्ल्यू० (2011)। रिसर्च इन एजुकेशन। नई दिल्ली: पी०एच०आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
12. राय, पी० & राय, सी० पी० (2012)। अनुसंधान परिचय। आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

वेबसाइट

www.google.com

www.sodhganga.inflibnet.ac.in

**देवेन्द्र सिंह चम्याल**

एम० एस-सी० रसायन विज्ञान, एम० ए० गणित, एम० ए० इतिहास, एम० एड० (गोल्ड मैडलिस्ट), नेट (शिक्षाशास्त्र), भोध छात्र एवं अतिथि व्याख्याता, शिक्षा संकाय, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल।